PK टाइम्स

लोक टूडे

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्षः 12 | अंकः 283 | मूल्यः 1.00 रुपए | पृष्ठः 4 | गुरुवार, 30 अप्रैल, 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

जयपुर मेट्रो फेज-2 को केंद्र की हरी झंडी

13037 करोड़ की मिली मंजूरी

■ केन्द्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी के 20 दिन बाद ही MoHUA ने जारी किया स्वीकृति आदेश, रिकॉर्ड मंजूरी

41 किलोमीटर में 36 नए स्टेशन बनेंगे

2031 तक पूरा करने का लक्ष्य

केंद्र-राज्य की 50-50 साझेदारी से बदलेगा जयपुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम

प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक मेट्रो विस्तार, ट्रैफिक और प्रदूषण में आएगी कमी

लोक टुडे। जयपुर

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने जयपुर मेट्रो फेज-2 की 13,037.66 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए औपचारिक स्वीकृति आदेश जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अथक प्रयासों से केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना की मंजूरी के 20 दिन बाद ही केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने यह स्वीकृति जारी कर गुलाबीनगरवासियों को सौगात दी है। इसके तहत 41 किलोमीटर लंबे इस उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर पर प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक कुल 36 स्टेशन बनाए जाएंगे।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नए आयाम होंगे स्थापित :

जयपुर के में सार्वजनिक परिवहन की जीवन रेखा जयपुर मेट्रो फेज-2 को गत 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी। यह परियोजना प्रधानमंत्री के विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करते हुए जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नए आयाम स्थापित करेगी।

जल्द मिलेंगे 12 किलोमीटर कॉरिडोर के लिए कार्यादेश :

केंद्रीय मंत्रिमंडल से फेज-2 को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की एक उच्च स्तरीय बैठक में इसके त्वरित क्रियान्वयन के लिए रस्ब्रष्टरुको शीघ्रता से आगे बढ़ने के निर्देश दिए थे। इसकी अनुपालना में परियोजना के प्रथम पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक के 12 किलोमीटर के कॉरिडोर के लिए कार्यादेश अतिशीघ्र जारी करने की तैयारी है। परियोजना के शेष पैकेज के लिए निविदाएं आगामी दिनों में जारी करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।

केन्द्र सरकार से मिलेगी 50 फीसदी हिस्सेदारी :

मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुरूप फेज - 2 परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से 50 प्रतिशत इक्विटी प्राप्त होगी, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार पर आने वाले वित्तीय भार में कमी आएगी। परियोजना को वर्ष 2031 तक पूर्ण करने का लक्ष्य लिया गया है। इस परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRCL) द्वारा किया जाएगा। RMRCL में केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत की साझेदारी है।

एक नजर में परियोजना :

- **लंबाई और मार्ग :** यह 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर होगा, जो प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ (हरमाड़ा) तक फैला होगा।
- **स्टेशनः** इस मार्ग पर कुल 36 स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से अधिकांश एलिवेटेड होंगे, जबकि हवाई अड्डा क्षेत्र में भूमिगत स्टेशन का प्रावधान है।
- **संचालनः** इसे राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, जो केंद्र और राज्य सरकार का 50-50 का संयुक्त उद्यम है।
- **समय सीमाः** परियोजना को सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

बंगाल- 7 एग्जिट पोल में से 5 में भाजपा सरकार

असम में बीजेपी, तमिलनाडु में डीएमके की वापसी

केरलम में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार का अनुमान

नई दिल्ली।

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं।

पांचों राज्यों में 3 से 12% मतदान बढ़ा

पांचों राज्यों में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई। सबसे बड़ा फैक्टर वोटर लिस्ट रिविजन (स्ढ्ढर) को बताया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए। इससे कुल वोटर्स की संख्या घट गई, लेकिन वोट डालने वाले लोगों की संख्या लगभग समान रही, जिससे प्रतिशत बढ़ गया। महिलाओं को कैश सहायता, मुफ्त यात्रा और आरक्षण जैसे वादों ने महिला वोटर्स को बड़ी संख्या में बाहर निकाला। इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में बंगाल-तमिलनाडु में 2', असम में 1', केरलम में 5' और पुडुचेरी में 3' ज्यादा रहा।

पश्चिम बंगालः

2021: 10 में से 5 एग्जिट पोल ने टीएमसी की जीत दिखाई, 3 ने बीजेपी की सरकार और 2 ने कड़ी टक्कर दिखाई।
2016: सभी 6 एग्जिट पोल ने ममता की वापसी की संभावना जताई।
2011: सर्वे एजेंसियां कम थीं। स्टार न्यूज-नीलसन, हेडलाइन टुडे और सीएनएन-आईबीएन-सीएसडीएस ने टीएमसी की जीत दिखाई।

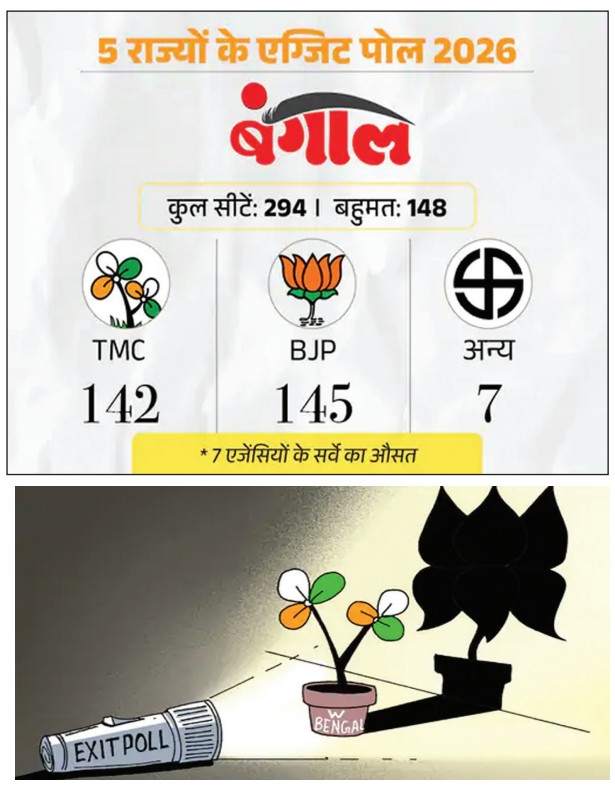

तमिलनाडु एग्जिट पोल्स 2026

कुल सीटें: 234 । बहुमत: 118

एजेंसी	DMK+	AIADMK+	टीवीके
पीपुल्स पल्स	125-145	65-80	18-24
मैट्रिज	122-132	87-110	10-12
जेवीसी- टाइम्स नाउ	75-95	128-147	8-15
पी मार्क	125-145	65-85	16-26
पीपुल्स इनसाइट	120-140	60-70	30-40
प्रजा पोल	148-168	61-81	1-9
एक्सिस माय इंडिया	92-110	22-32	98-120
कामाख्या एना.	78-95	68-84	67-81
वोट वाइब	103-113	114-124	4-10
एवरेज	**118**	**82**	**34**

रीको औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा और सुविधाओं को मिलेगा नया आयाम

जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास समग्र रूप से किया जा रहा है, जिसमें विद्युत की निर्बाध उपलब्धता, सड़कों के निर्माण एवं सुधार, अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का आधुनिक एवं सुदृढ़ विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में रीको प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, उन्नयन एवं रखरखाव पर लगभग 1500 करोड़ रुपये से अधिक व्यय अपेक्षित है, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को और मजबूत बनाया जा सके।

औद्योगिक इकाइयों को आगजनी जैसी आपदाओं से सुरक्षित रखने एवं बेहतर सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से रीको द्वारा 12 नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना तथा 37 अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। प्रस्तावित अग्निशमन केंद्र भिवाड़ी (चौपानकी, खुशखेड़ा), बीकानेर (करणी औद्योगिक क्षेत्र चरण प्रथम एवं द्वितीय), बोरानाडा, चुरू, जयपुर (जैतपुरा), जोधपुर (बासनी), नागौर (आईआईडी सेंटर एवं एसजीसी परबतसर), सवाई माधोपुर (खेरदा, टोंक, हिंडौन सिटी) तथा श्रीगंगानगर में औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ (चरण द्वितीय) सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त आबूरोड, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बीकानेर, बोरानाडा, चुरू, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, नागौर, नीमराना, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में 37 अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की जाएगी।

रीको द्वारा विद्युत आपूर्ति को निर्बाध एवं सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्य भी करवाये जायेंगे।

रीको के इन प्रयासों से राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण का निर्माण होगा, जिससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

ट्रम्प की राइफल के साथ फोटो, ईरान को धमकी दी

तेहरान/वॉशिंगटन डीसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने राइफल के साथ फोटो शेयर कर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जल्दी समझदार बनो, अब ज्यादा देर नरमी नहीं बरती जाएगी। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राइफल के साथ एक फोटो पोस्ट की। फोटो पर लिखा था, 'नो मोर मिस्टर नाइस गा' यानी अब ज्यादा देर नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई और कहा कि ईरान खुद को संभाल नहीं पा रहा है। ट्रम्प ने कहा है कि अगर जल्द कोई समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिका और सख्त रुख अपना सकता है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चिट्ठी में ईरान ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके जहाजों को जब्त करके 'समुद्री डकैती' की है। UAE ने ओपेक छोड़ाः संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 1 मई से तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक से 59 साल बाद बाहर निकलने की ऐतिहासिक घोषणा की है। ओपेक दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों का समूह है।

हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत 25 मई तक बढ़ाई

जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि 25 मई तक बढ़ा दी है। आसाराम की जमानत अवधि 6 मई को खत्म हो रही थी। आसाराम ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया था। उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने बुधवार को आसाराम की जमानत अवधि को मेडिकल ग्राउंड पर 25 मई तक बढ़ाने के निर्देश दिए। आसाराम की ओर से पैरवी करते हुए उनके अधिवक्ता यशपाल राजपुरोहित ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट उनकी अपील पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख चुका है। उन्होंने कहा- आसाराम का इलाज अभी जारी है। ऐसे में इलाज पूरा होने तक जमानत की अवधि बढ़ाई जाए।

1 मई से 15 मई, 2026 तक स्व-गणना पोर्टल पर जाकर अपने और परिवार की जानकारी दर्ज करने का किया आह्वान

जयपुर

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जनगणना के लिए 1 मई से 15 मई, 2026 तक स्व-गणना पोर्टल पर जाकर अपनी और परिवार की सटीक जानकारी दर्ज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 16 मई से 14 जून तक गणनाकर्मी प्रदेश के लोगों के पास घर-घर पहुंचेंगे। पहले चरण में मोबाइल ऐप से आवासों की सूची, सुविधाओं, संपत्तियों और अन्य आवश्यक आंकड़े एकत्रित होंगे।

राज्यपाल बागडे ने कहा कि 'जनगणना' का अर्थ लोगों की गिनती भर नहीं है। 'जनगणना' का अर्थ है- शिक्षा, रोजगार, लिंग अनुपात, और जातिगत आंकड़ो के आधार पर राष्ट्र का सामाजिक दस्तावेज तैयार करना। इसी से भारत में जन-जन के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास योजनाओं और बेहतरीन नीतियों को लागू किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री की प्रदेशवासियों से अपील : जनगणना संवैधानिक दायित्व, इसे राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर पूरा करें

राजस्थान में जनगणना महाअभियान 16 मई से होगा शुरू

सटीक जानकारी देकर राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बनें भागीदार

डिजिटल इंडिया का विजन हो रहा साकार, 1 मई से नागरिकों को स्व-गणना की भी सुविधा

जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से भारत की 'जनगणना 2027' में अपनी सहभागिता निभाने के लिए अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन मात्र नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महान राष्ट्रीय यज्ञ है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि जनगणना में सहभागिता को सामाजिक न्याय के अवसर के रूप में अपनाएं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना कार्मिक लंबी दूरियां तय करके लोगों तक पहुंचेगे, ऐसे में आमजन जनगणना के कार्य में उनका सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि मकान और परिवार से संबंधित सटीक, सत्य और पूर्ण जानकारी प्रदान कर इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति दें।

उन्होंने बताया कि राजस्थान में जनगणना 2027 का प्रथम चरण मई से शुरू हो रहा है। इसके तहत मकानों की सूची और गणना का कार्य 16 मई से 14 जून तक किया जाएगा। इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। प्रदेशवासी आवश्यक सहयोग करते हुए मकानों की गणना से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर देकर अपना दायित्व निभाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाते हुए 1 मई से 15 मई के बीच नागरिकों को स्व-गणना की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने आग्रह किया कि प्रत्येक नागरिक इस सुविधा का लाभ उठाएं और ह्यद्र.ष्द्गठ्ठह्यह्वह्य.द्दश1.द्बठ्ठ पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी दर्ज कर इस राष्ट्रीय दायित्व के सहभागी बनें। गौरतलब है कि सटीक जनगणना विकास योजनाओं का एक महत्वपूर्ण आधार है। जनगणना के समय संकलित आंकड़ों से ही केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का निर्धारण एवं क्रियान्वयन प्रभावशाली ढंग से संभव हो पाता है। सरकार को पुख्ता आंकड़ों से ही गांव-शहरों के व्यक्तियों और परिवारों की स्थिति, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, स्कूल, चिकित्सालय, घरेलू गैस कनेक्शन आदि की उपलब्धता और आवश्यकता के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे में सभी नागरिक अपना सक्रिय योगदान देते हुए जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

सम्पादकीय

"मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो
विस्तारस्वतंत्रता का हनन न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार"

असमय गर्मी के तीखे तेवर

अप्रैल में ही छूटा पसीना, टूटा रिकॉर्ड

मौसम की अपनी गति होती है और उसमें उतार-चढ़ाव की वजहें भी प्रकृति के चक्र का हिस्सा होती हैं। मगर पिछले काफी समय से जिस तरह वैश्विक ताप में बढ़ोतरी की वजह से गर्मी के दिनों में जटिलताएं खड़ी हो रही हैं, वह निश्चित रूप से दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हर वर्ष अप्रैल में गर्मी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस साल तापमान के जो तेवर दिख रहे हैं, उससे यह साफ है कि मौसम में यह उतार-चढ़ाव सामान्य नहीं है। समूचे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है और कई शहरों में तापमान चालीस से बयालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। जिन दिनों लोग मई-जून की तेज गर्मी के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं, उनका शरीर धीरे-धीरे अभ्यस्त हो रहा होता है, उसमें हालत यह है कि चिलचिलाती धूप की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है और मौसम विभाग की ओर से सतर्क रहने के लिए चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। उसने जो पूर्वानुमान जारी किया, उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में मिला-जुला मौसम बना रहेगा, जिसमें कहीं भीषण गर्मी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी, तो कहीं थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में लू, उमस भरी गर्मी और गर्म रातों में आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं कुछ इलाकों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। मौसम की अपनी गति होती है और उसमें उतार-चढ़ाव की वजहें भी प्रकृति के चक्र का हिस्सा होती हैं। मगर पिछले काफी समय से जिस तरह वैश्विक ताप में बढ़ोतरी की वजह से गर्मी के दिनों में जटिलताएं खड़ी हो रही हैं, वह निश्चित रूप से दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिल्ली में इस गर्मी में अधिकतम तापमान पैंतालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो आमतौर पर मई के उत्तरार्ध और जून में दर्ज किया जाता रहा है। इस वर्ष पश्चिमी विक्षोभ और तूफानों में भी कमी देखी गई, वहीं पिछले अल-नीनो के प्रभाव की वजह से गर्मी में सामान्य से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगले दो-तीन दिनों में हल्की बारिश और मौसम में बदलाव का अनुमान है, लेकिन जाहिर है, तापमान में व्यापक उथल-पुथल और लू की आशंकाओं के बीच तेज धूप में निकलने से बचने, पानी पीते रहने और अन्य स्तर पर सावधानी ही बचाव का बेहतर उपाय है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राजधानी दिल्ली में आगामी 29 अप्रैल को तेज आंधी-तूफान संग बारिश की 'पीली चेतावनी' जारी की है। पूरे दिन घने बादल छाए रहने के साथ ही गरज, बिजली व तेज हवाओं संग एक से दो बार बारिश होने की संभावना है।

रक्षा खर्च बढ़ाने की बाध्यता

आज के लोकतांत्रिक युग में किसी देश से यह अपेक्षित नहीं कि वह विस्तारवादी अथवा सामंतवादी मानसिकता का परिचय दे, पर समस्या यह है कि ऐसी मानसिकता वाले देशों की कमी नहीं।

स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी की इस रिपोर्ट पर आश्चर्य नहीं कि 2025 में विश्व का कुल सैन्य खर्च 2024 के मुकाबले 2.9 प्रतिशत अधिक रहा। अब रक्षा खर्च विश्व की कुल जीडीपी का 2.5 प्रतिशत हो गया है। इस संस्था की रिपोर्ट यह भी बताती है कि रक्षा खर्च में भारत विश्व में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। चूंकि भारत विश्व की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति है, इसलिए रक्षा खर्च के मामले में उसका पांचवें स्थान पर होना हैरानी का विषय नहीं। भारत रक्षा खर्च में कटौती इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश उसके लिए समस्या बने हुए हैं। चूंकि वैश्विक परिदृश्य बदलने के साथ लड़ाई के तौर-तरीके भी बदल रहे हैं, इसलिए अपनी सेना के आधुनिकीकरण के चलते भी भारत को रक्षा खर्च बढ़ाना पड़ रहा है। वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए यह संभव नहीं कि वह अपने रक्षा खर्च में कमी करे। भारत की तरह अन्य कई देशों को भी अपने समक्ष उभर रहे खतरों के कारण अपना रक्षा खर्च बढ़ाना पड़ रहा है। कुछ ऐसे भी देश हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद भी पड़ोसी देशों पर अपना दबदबा कायम करने अथवा उन्हें आतंकित करने के लिए अपना रक्षा खर्च बढ़ाने में जुटे रहते हैं। दुर्भाग्य से पड़ोसी पाकिस्तान ऐसे देशों में प्रमुख है। चीन भी अंधाधुंध तरीके से रक्षा पर खर्च कर रहा है, ताकि एशिया के साथ विश्व में अपना वर्चस्व कायम कर सके। आज के लोकतांत्रिक युग में किसी देश से यह अपेक्षित नहीं कि वह विस्तारवादी अथवा सामंतवादी मानसिकता का परिचय दे, पर समस्या यह है कि ऐसी मानसिकता वाले देशों की कमी नहीं। ऐसे देशों के समक्ष वैश्विक संस्थाएं और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिस तरह असहाय-निरुपाय है, उसके चलते भी हथियारों की होड़ बढ़ रही है और तमाम देशों को जो पैसा अपने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में खर्च करना चाहिए, वह सैन्य संसाधन जुटाने में खपाना पड़ता है। पिछले कुछ समय से प्रमुख वैश्विक शक्तियां जिस तरह मनमानी कर रही हैं, उससे अभी तक चली आ रही विश्व व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी है। जैसे यूक्रेन पर रूस का हमला, उसकी मनमानी का परिचायक था, वैसे ही अमेरिका की ओर से पहले वेनेजुएला और फिर ईरान को निशाना बनाना भी उसका मनमानापन ही है। बड़े देशों की यह मनमानी भी रक्षा खर्च की होड़ बढ़ा रही है। भारत चाहकर भी अपना रक्षा खर्च कम नहीं कर सकता, लेकिन उसकी प्राथमिकता अपनी आवश्यकता की अधिकाधिक युद्धक सामग्री का निर्माण देश में ही करना होना चाहिए। इससे देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा और रक्षा खर्च में कमी भी आएगी।

संतुलन पर टिका व्यापार समझौता

अनंत स्वरूप

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए का मूर्त रूप लेना भारत की व्यापारिक कूटनीति में महत्वपूर्ण कदम है। यह इसका भी स्पष्ट संकेत है कि देश पूरे आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर जुड़ाव के लिए तैयार है। भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ और अधिक गहराई से जुड़ने का इच्छुक होने के साथ यह सुनिश्चित करने में भी लगा है उसके किसानों, श्रमिकों, छोटे उद्यमों यानी एमएसएमई और रणनीतिक क्षेत्रों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। यह समझौता पिछले वर्ष मार्च में आरंभ हुई वार्ताओं का परिणाम है, जिस पर दिसंबर में ही सहमति बन गई थी और सोमवार को उस पर हस्ताक्षर भी हो गए। यह कवायद आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में दोनों पक्षों की प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतीक बनकर भी उभरी है। भारत के लिए यह समझौता केवल इसलिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह एक उच्च आमदनी वाले और व्यापार एकीकृत बाजार में नए अवसर खोलता है, बल्कि इस दृष्टि से भी महत्व रखता है कि इसके माध्यम से भारत के ओशियानिया और प्रशांत क्षेत्र में संबंधों को नया आयाम मिलेगा। अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1.3 अरब डालर के द्विपक्षीय व्यापार में भारत को ही बढ़त की स्थिति प्राप्त है, मगर न्यूजीलैंड के 47.5 अरब डालर के आयात में भारत की हिस्सेदारी मात्र दो प्रतिशत के मामूली स्तर पर है। पहले भारतीय उत्पादों पर 10 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगता था, लेकिन एफटीए से ये समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। व्यापक रूप से देखें तो भारत-न्यूजीलैंड एफटीए भविष्य को ध्यान में रखने वाला समझौता है, जो वस्तुओं और सेवाओं के साथ ही गतिशीलता एवं नवाचार को ध्यान में रखता है। न्यूजीलैंड भारतीय निर्यातों के लिए सभी टैरिफ लाइनों पर निःशुल्क पहुंच प्रदान करने जा रहा है, जिसमें वस्त्र, परिधान, चमड़े के सामान, कालीन, आटोमोबाइल और कलपुर्जों पर ऊंचे टैरिफ समाप्त कर दिए गए हैं। इसके बदले में भारत लगभग 70 प्रतिशत शुल्क श्रेणियों में सीमित बाजार प्रवेश देगा और 30 प्रतिशत श्रेणी में शुल्क तत्काल समाप्त करेगा, जबकि शेष श्रेणियों में इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। भारत ने लगभग 30 प्रतिशत संवेदनशील 'टैरिफ लाइनों' को इस सूची से बाहर रखा है, ताकि घरेलू हितों की रक्षा की जा सके। इसमें डेरी उत्पादों, दालों, चीनी, खाद्य तेल, प्याज, मक्का और बादाम जैसी श्रेणियों को संरक्षण प्रदान किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा के साथ ही किसानों के हितों को संबोधित करते हैं। अनूठी विशेषताएं इस एफटीए को और आकर्षण प्रदान करती हैं।

समझौते की ताकत इसके संतुलन और आपसी संवेदनाओं की मान्यता में निहित है। भारतीय कृषि क्षेत्र की संवेदनाओं को समझते हुए न्यूजीलैंड कीवी फल, सेब और शहद उत्पादन के लिए कार्य योजनाओं और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना में भी सहयोग करेगा।

जैसे न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डालर के निवेश की बात की है। यह निवेश मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इसमें एक पुनर्संतुलन का भी प्रविधान है, जो निवेश लक्ष्य पूरे न होने की स्थिति में भारत को उपचारात्मक उपाय करने की अनुमति देता है। यह कदम रोजगार, तकनीक हस्तांतरण और आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण को बढ़ावा देगा, जिसमें न्यूजीलैंड के मजबूत विदेशी निवेश प्रोफाइल का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, न्यूजीलैंड ओशियानिया-प्रशांत बाजारों और स्थापित वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के लिए एक रणनीतिक प्रवेश-द्वार (गेटवे) की भूमिका भी निभाएगा। भारतीय प्रतिभाओं के लिए भी यह बहुत उपयोगी साबित होने जा रहा है। इसमें भारतीय छात्रों के लिए वीजा की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उन्हें पढ़ाई के दौरान 20 घंटे काम करने और पढ़ाई के बाद भी चार साल तक के लिए प्रभावी वीजा दिया जाएगा। न्यूजीलैंड ने किसी एफटीए में पहली बार इस तरह का कोई प्रविधान किया है। एक नई अस्थायी रोजगार प्रवेश श्रेणी के तहत आइटी, स्वास्थ्य सेवा और इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए 5,000 प्रोफेशनल वीजा भी सुनिश्चित किए गए हैं। इसमें आयुष चिकित्सकों, योग प्रशिक्षकों, भारतीय रसोइयों और संगीत शिक्षकों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए भी तीन साल तक के वीजा का प्रविधान है। ये कदम लोगों के बीच यानी पीटूपी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों यानी बीटूबी संबंधों की काया पलटने की क्षमता रखते हैं। वस्त्र-परिधान क्षेत्र को इस एफटीए से बड़ा संबल मिलने जा रहा है। न्यूजीलैंड हर साल 1.2 अरब डालर के परिधान आयात करता है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी केवल चार प्रतिशत है, जो इस एफटीए के बाद परवान चढ़ती दिखेगी। चमड़ा और फुटवियर के अलावा रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्र भी इसके बड़े लाभार्थी बनकर उभरेंगे, जहां पूर्ववर्ती टैरिफ भारतीय उत्पादों की संभावनाओं की राह में अवरोध बन रहे थे। इसी तरह इंजीनियरिंग वस्तुओं के 6.6 अरब डालर के बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी महज एक प्रतिशत रही, वह भी बढ़ने के भरे-पूरे आसार हैं। फार्मा बाजार में भी भारत की केवल 5.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी को भी एफटीए के बाद और विस्तार मिलेगा। समझौते की ताकत इसके संतुलन और आपसी संवेदनाओं की मान्यता में निहित है। भारतीय कृषि क्षेत्र की संवेदनाओं को समझते हुए न्यूजीलैंड कीवी फल, सेब और शहद उत्पादन के लिए कार्य योजनाओं और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना में भी सहयोग करेगा।

पंजाब से दिल्ली तक सियासी 'सुनामी' : संकट में आप

भारत की समकालीन राजनीति में शायद ही कोई घटना इतनी तेजी से राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आई हो, जितनी राघव चड्ढा सहित सात राज्यसभा सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से आई है। राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों का भाजपा में विलय केवल एक खबर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के 15 साल के इतिहास का सबसे बड़ा %ब्लैकआउट% है। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर यह घटनाक्रम एक बड़े 'पॉलिटिकल अर्थक्वेक' के रूप में दर्ज हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के 'पोस्टर बॉय' माने जाने वाले राघव चड्ढा सहित राज्यसभा के 7 सांसदों का एक साथ पाला बदलकर भाजपा में शामिल होना न केवल 'आप' के लिए एक अस्तित्वगत संकट है बल्कि यह देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाला घटनाक्रम भी है। यह सिर्फ दल-बदल नहीं बल्कि सत्ता, विचारधारा और राजनीतिक रणनीति के बीच गहरे संघर्ष का संकेत है। जब राज्यसभा में पार्टी के कुल 10 में से 7 सांसद (दो-तिहाई बहुमत) एक साथ अलग होकर भाजपा में विलय करने का निर्णय लेते हैं तो यह दलबदल नहीं, एक वैचारिक और संगठनात्मक विद्रोह का प्रतीक बन जाता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय राजनीति 2027 के बड़े चुनावी चक्र की ओर बढ़ रही है। ऐसे में इस घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या 'आप' का 'पंजाब किला' अब ढहने के कगार पर है? क्या 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की पटकथा अभी से लिखी जा चुकी है? और सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या यह 'आप' के पतन की शुरुआत है या फिर एक अस्थायी राजनीतिक झटका? आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल राजनीतिक असहमति नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सुनियोजित प्रहार करार दिया है। पार्टी नेतृत्व का स्पष्ट आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों के भय, दबाव और राजनीतिक प्रलोभनों के माध्यम से उसके सांसदों को तोड़ा गया, जिसे वह संस्थागत दुरुपयोग की श्रेणी में रखती है। यह आरोप भारतीय राजनीति में सत्ता बनाम विपक्ष की उस पुरानी बहस को फिर जीवित कर देता है, जहां नैतिकता और रणनीति आमने-सामने खड़ी दिखाई देती हैं। संवैधानिक दृष्टि से यह कदम और भी दिलचस्प हो जाता है। दलबदल विरोधी कानून की तकनीकी बारीकी (दो-तिहाई सदस्यों के एक साथ अलग होने की शर्त) का उपयोग करते हुए राघव चड्ढा के नेतृत्व में सात सांसदों का भाजपा में विलय यह संकेत देता है कि यह केवल भावनात्मक निर्णय नहीं बल्कि गहन कानूनी सलाह और रणनीतिक योजना का परिणाम था। सबसे

आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल राजनीतिक असहमति नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सुनियोजित प्रहार करार दिया है। पार्टी नेतृत्व का स्पष्ट आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों के भय, दबाव और राजनीतिक प्रलोभनों के माध्यम से उसके सांसदों को तोड़ा गया, जिसे वह संस्थागत दुरुपयोग की श्रेणी में रखती है।

गंभीर आघात वैचारिक स्तर पर है। जब भीतर से ही यह स्वर उठे कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है तो यह केवल संगठनात्मक संकट नहीं बल्कि पहचान के संकट का संकेत बन जाता है और यही चुनौती 'आप' के लिए सबसे कठिन परीक्षा है। पंजाब की राजनीति में उठी यह हलचल महज दल-बदल नहीं बल्कि सत्ता समीकरणों के पुनर्गठन का संकेत है। इस विद्रोह का सबसे गहरा असर पंजाब की सियासत पर पड़ना तय है। राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे (हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा और विक्रमजीत सिंह साहनी) का पार्टी से अलग होना 'आप' की उस सामाजिक पकड़ को कमजोर करता है, जो विविध वर्गों के प्रतिनिधित्व से बनी थी। यह बदलाव केवल संख्या का नहीं बल्कि भरोसे और प्रभाव का क्षरण है। सबसे बड़ी चुनौती भगवंत मान के सामने है। यह उनके नेतृत्व और राजनीतिक संतुलन की सीधी परीक्षा है। राघव चड्ढा को लंबे समय तक सरकार और संगठन के बीच रणनीतिक कड़ी माना जाता रहा, उनके हटने से यह संतुलन डगमगाता दिख रहा है। दूसरी ओर, भाजपा इस घटनाक्रम को अवसर में बदलने की कोशिश में है। भाजपा पंजाब में हमेशा से एक %छोटा भाई% (अकाली दल के साथ) बनकर रही है लेकिन 7 सांसदों के आने से, जिनमें सिखों और उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व है, भाजपा अब 2027 में %अकेले दम% पर सरकार बनाने का सपना देख रही है। अब तक सहयोगी राजनीति तक सीमित रही भाजपा अब पंजाब में स्वतंत्र शक्ति बनने की दिशा में आक्रामक कदम बढ़ाती दिख रही है और 2027 का रण अब पहले से कहीं अधिक खुला और अनिश्चित हो गया है। इतिहास गवाह है कि क्षेत्रीय दल जब ऐसे बड़े विद्रोह का सामना करते हैं तो अक्सर वे या तो बिखर जाते हैं या फिर सिमटकर रह जाते हैं लेकिन आप की स्थिति थोड़ी भिन्न है। इसका सबसे बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल का व्यक्तित्व। आम आदमी पार्टी का आधार अरविंद केजरीवाल की 'व्यक्तिगत ब्रांडिंग' पर टिका है। जब तक दिल्ली और पंजाब जैसे अहम राज्यों में उनका जनाधार सुरक्षित है, तब तक 'आप' का पूर्ण पतन लगभग असंभव प्रतीत होता है। इसके समानांतर, 'आप' की ताकत उसका विकसित कैडर ढांचा है। आप ने पिछले एक दशक में एक मजबूत कैडर तैयार किया है। हालांकि शीर्ष स्तर पर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और अब राघव चड्ढा जैसे प्रमुख चेहरों का अलग होना पार्टी को बड़ा झटका देता है लेकिन जमीनी कार्यकर्ता अब भी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं। एक वैकल्पिक, जनोन्मुख और व्यवस्था-विरोधी नेता की केजरीवाल की छवि अब भी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी बनी हुई है। राष्ट्रीय राजनीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह घटनाक्रम सत्ता-संतुलन को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। राज्यसभा में सात सांसदों के जुड़ने से भाजपा की स्थिति और सुदृढ़ हुई है, जिससे अब महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने में उसकी छोटे दलों पर निर्भर रहने की बाध्यता कम हो गई है। इसके विपरीत, विपक्षी गठबंधन के लिए यह स्पष्ट झटका है क्योंकि 'आप' इस गठबंधन की मुखर आवाज रही है। सबसे गंभीर आघात 'आप' की वैचारिक विश्वसनीयता पर पड़ा है। जो पार्टी 'ईमानदार राजनीति' को अपनी पहचान मानती रही, उसी के भीतर से वैचारिक विचलन और आरोपों का उठना उसके नैरेटिव को कमजोर करता है। यह स्थिति नेतृत्व शैली पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है, लगातार बड़े चेहरों का अलग होना इस ओर संकेत करता है कि संवाद की कमी और निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण आंतरिक असंतोष को जन्म दे रहा है। राष्ट्रीय विस्तार की महत्वाकांक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ना तय है। दिल्ली और पंजाब से आगे बढ़ने की जो रणनीति थी, वह अब धीमी पड़नी तय है, विशेषकर तब, जब पंजाब, जो 'आप' का सबसे मजबूत गढ़ है, स्वयं इस राजनीतिक भूकंप के केंद्र में आ खड़ा हुआ है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि 7 सांसदों के जाने से आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। राजनीति में रिक्तियां हमेशा भर दी जाती हैं।

महाशक्ति की सुरक्षा में सेंध

ट्रंप पर हमले ने खड़े किए गंभीर सवाल

अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित रात्रिभोज में गोलीबारी की घटना ने दुनिया भर में सबके कान खड़े कर दिए हैं। यह वारदात ऐसे मौके पर हुई, जब यहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी एवं प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। हालांकि बाद में सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल है कि विश्व की महाशक्ति होने का दंभ भरने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में अपने ही देश के भीतर इस तरह की चूक कैसे हो सकती है? कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हमलावर आयोजन स्थल में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हो गया! गोलीबारी की वजह से पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई और ट्रंप को उनकी पत्नी के साथ तत्काल सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। यह घटना सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम देशों के लिए भी सबक है, जो मानते हैं कि उनके शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा अभेद्य है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमलावर ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन यहां राष्ट्रपति की मौजूदगी से मामले की गंभीरता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप पर पहले भी दो बार हमले हो चुके हैं, हालांकि यह बात अलग है कि उस दौरान वे अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर नहीं थे। मार्च 2016 में लास वेगास में राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के दौरान रैली में एक व्यक्ति ने मंच के पास पहुंचकर ट्रंप की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी का हथियार छीनने की कोशिश की थी। हिरासत में पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि वह ट्रंप को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसके बाद जुलाई 2024 में चुनावी रैली में ट्रंप पर उस समय खतरनाक हमला हुआ था, जब वह मंच से भाषण दे रहे थे। मगर गनीमत रही कि हमलावर की ओर से चलाई गई गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई। यह बात समझ में आती है कि इन दो घटनाओं के दौरान ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, इसलिए उनकी सुरक्षा का दायरा उतना बड़ा नहीं था, लेकिन उनके राष्ट्रपति होते हुए अगर सुरक्षा में किसी तरह की चूक होती है, तो व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है।

परिवर्तन को तैयार दिखता बंगाल

बंगाल सिर्फ वोट नहीं डाल रहा है। वह अपने लोकतांत्रिक भविष्य की नई दिशा भी तय करता दिख रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के सघन संशोधन का जो अभियान चलाया, उससे राज्य भर से बड़े पैमाने पर संदिग्ध, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया का सख्त और पारदर्शी होना केवल मतदान तक सीमित नहीं है। यह उस औपचारिक राज्य की वापसी है, जो लंबे समय तक स्थानीय शक्ति संरचनाओं के पीछे छिप गया था। मतदाता परिणाम और सुशासन के आधार पर सत्ता की वैधता तय करना चाहता है। राजनीति विज्ञान का एक सीधा नियम है कि जहां अनौपचारिक शक्ति संरचनाएं और सिंडिकेट हावी होते हैं, वहां राज्य की औपचारिक क्षमता पूरी तरह कमजोर हो जाती है। यही स्थिति बंगाल में निवेश और विकास की सबसे बड़ी बाधा बन गई है। जो बंगाल कभी औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, वह आज रोजगार देने में काफी पिछड़ चुका है। जब भी कोई नया कारखाना या उद्यम शुरू होता है, स्थानीय बाहुबली उसमें दखल देते हैं। इससे निवेशक पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। जनता अब ऐसा तंत्र चाहती है, जो पारदर्शी हो और औपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूती दे। यह चुनाव एक गहरे सामाजिक और पीढ़ीगत बदलाव का भी गवाह बन रहा है। नई पीढ़ी राजनीतिक निष्ठा के बजाय अवसरों के आधार पर प्राथमिकताएं तय कर रही है। आज का युवा मतदाता पारंपरिक झंडों और नारों का मोहताज नहीं है। उसे एक ऐसा तंत्र चाहिए जिस पर वह विश्वास कर सके। वह बेंगलुरु, पुणे या दिल्ली जैसी सुविधाओं और अवसरों को अपने ही राज्य में देखना चाहता है। जब यह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो उसका गुस्सा सत्ता के खिलाफ मुखर होता है। राष्ट्रवाद, पारदर्शिता और विकास की राजनीति का जो नया विकल्प राज्य में उभर रहा है, वह इसी

युवा वर्ग की आकांक्षाओं को स्वर देता दिख रहा है। राजनीति में नागरिक और सरकार के रिश्ते के मायने भी तेजी से बदल रहे हैं। सरकार की मुफ्त राशन और नकद सहायता जैसी योजनाओं ने समाज के निचले तबके को फौरी राहत जरूर दी है, लेकिन अर्थशास्त्र और राजनीति का यह अनुभव बताता है कि एक सीमा के बाद कल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिक प्रभाव घटने लगता है। खासकर तब, जब वे जनता की नई आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पातीं। जब सरकार नागरिकों को स्थायी रूप से केवल 'लाभार्थी' मानकर चलने लगती है तो बुनियादी विकास पीछे छूट जाता है। यह निर्भरता समाज को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देती। बंगाल का मतदाता अब कुछ सौ रुपयों की मासिक सहायता से आगे पक्का रोजगार और अपनी मेहनत का सम्मानजनक मोल चाहता है। सशक्तीकरण का यही माडल अब बंगाल के विमर्श में जगह बनाता प्रतीत हो रहा है। जनसांख्यिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसी चिंताएं बन चुकी हैं, जिन्हें अब किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ के आरोप और उनसे जुड़ी चिंताओं ने राज्य की सामाजिक पहचान पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। संदेशखाली जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सत्ता के करीब माने जाने वाले स्थानीय बाहुबलियों ने जिस प्रकार महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई, उसने बंगाली भद्रलोक और ग्रामीण समाज को भीतर तक आहत किया। यह एक विशेष प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा नतीजा है। राज्य का एक वर्ग कह रहा है कि इस तरह की नीतियों में कानून के समान शासन की पूरी तरह अनदेखी हो रही है। उत्तर बंगाल के राजबंशी समुदाय से लेकर मतुआ समाज तक, सभी अपनी अस्मिता और अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। बंगाल की राजनीति में लंबे अरसे तक राजनीतिक हिंसा का इस्तेमाल अपना दबदबा बनाए रखने के हथियार के रूप में हुआ है। चुनाव से पहले लोगों को डराना और विरोधियों को निशाना बनाना यहां का कड़वा सच रहा है, लेकिन इस बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भारी तैनाती और चुनाव आयोग के सख्त रवैये ने डर के उस माहौल को काफी हद तक खत्म कर दिया है। इसी सुरक्षित माहौल में बंगाल में एक मौन मतदाता उभर रहा है। यह वह मतदाता है, जो सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहता, लेकिन मतदान केंद्र पर अपनी स्वतंत्र पसंद दर्ज करता है। बिना किसी डर या दबाव के मतदान करने की यह हिम्मत एक परिपक्व होते लोकतंत्र का बहुत शुभ संकेत है। बंगाल की धरती पर चल रहा यह मंथन केवल एक सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन की पदचाप है। बड़े पैमाने पर संदिग्ध वोटरों के नाम हटना, न्यायपालिका की सख्ती, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और सुशासन की मुखर मांग बता रही है कि राज्य बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जनता के सामने दो रास्ते हैं।

सीएम का वीडियो मैसेज : कल से शुरू होगी जनगणना, आमजन निभाए भागीदारी

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान की राजनीति और प्रशासन में इन दिनों डिजिटल गवर्नेंस की नई बयार चल रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार की सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रदेशवासियों के नाम एक वीडियो मैसेज जारी किया। मुख्यमंत्री का यह संदेश एक दिन बाद शुक्रवार 1 मई से आधिकारिक रूप से शुरू होने जा रही जनगणना 2027 को लेकर साझा किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएं ताकि राज्य के विकास की सटीक रूपरेखा तैयार की जा सके।

1 मई से 14 जून तक होगी जन और मकानों की गणना :

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में जनगणना की समय-सीमा को लेकर पूरी स्पष्टता दी है, ताकि प्रदेशवासियों को किसी प्रकार का भ्रम न रहे। 1

मई से 15 मई 2026 तक नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने आधिकारिक लिंक भी जारी किया है। 16 मई से 14 जून 2026 तक जनगणना कर्मी राजस्थान के कोने-कोने में घर-घर जाकर मकानों की सूची तैयार करेंगे और आवश्यक डेटा संकलित करेंगे।

तपती धूप और लम्बी दुरी होगी चुनौती :

मुख्यमंत्री ने राजस्थान की भौगोलिक चुनौतियों और सांस्कृतिक मूल्यों का जिक्र करते हुए एक भावुक अपील भी की। उन्होंने कहा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। हमारे जनगणना कर्मी तपती धूप में लंबी दूरी तय कर आपके द्वार आएंगे। सीएम ने आह्वान किया कि राजस्थान की अतिथि सत्कार की परंपरा को निभाते हुए कर्मियों को सही और सटीक जानकारी प्रदान करें। सीएम ने जोर दिया कि आपके द्वारा दी गई सही सूचना ही भविष्य में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि यह संसाधनों के बंटवारे और नई योजनाओं का आधार है। मुख्यमंत्री का सुबह-सुबह यह संदेश देना संकेत देता है कि सरकार इस बार डेटा संकलन में 'जीरो एरर' चाहती है।

राज्यपाल की भी अपील :

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जनगणना के लिए 1 मई से 15 मई तक स्व-गणना पोर्टल पर जाकर अपनी और परिवार की सटीक जानकारी दर्ज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 16 मई से 14 जून तक गणनाकर्मी प्रदेश के लोगों के पास घर-घर पहुंचेंगे। पहले चरण में मोबाइल ऐप से आवासों की सूची, सुविधाओं, संपत्तियों और अन्य आवश्यक आंकड़े एकत्रित होंगे।

रंग दे गुलाबी अभियान में 2 मई को एक ही दिन रंगी जाएगी शहर की 500 दीवारें

लोक टुडे। जयपुर

नगर निगम जयपुर ने नवाचारों की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम रखते हुए 2 मई को रंग दे गुलाबी अभियान की घोषणा की। इस अभियान के तहत देश में पहली बार एक ही दिन में 500 दीवारें रंगने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई यह पहल शहर की सुंदरता को नई पहचान देने के साथ-साथ जनभागीदारी का एक बड़ा उदाहरण बनेगी। नगर निगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर निगम आयुक्त ने इस महत्वाकांक्षी अभियान को जयपुर के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताया। आयुक्त ने बताया कि सफाई सेवा मैराथन से स्वच्छता की दिशा में मजबूत आधार स्थापित करने के बाद अब शहर को और अधिक आकर्षक और जीवंत बनाने की दिशा में यह अगला कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रंग दे गुलाबी केवल गुलाबी रंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य गुलाबी नगरी जयपुर को विभिन्न रंगों से और अधिक सुंदर, सृजनात्मक और जीवंत बनाना है। शहर की दीवारों पर पारंपरिक गुलाबी के साथ-साथ आकर्षक और कलात्मक रंगों का उपयोग किया जाएगा, जिससे हर क्षेत्र अपनी अलग पहचान के साथ उभरे और शहर की सांस्कृतिक विरासत का आधुनिक स्वरूप सामने आए। इस अभियान में स्कूल, कॉलेज, एनजीओ, निजी संस्थाएं, कॉर्पोरेट समूह और आम नागरिक स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं। विशेष रूप से पेंटिंग सेवाएं देने के इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थाएं 7470651609 एवं 7878252518 पर संपर्क कर सकते हैं। इस अभियान के अंतर्गत चिन्हित सभी 500 दीवारों की जानकारी पेंटिंग से पहले और बाद में मीडिया एवं आमजन के साथ साझा की जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। नगर निगम जयपुर ने सभी जयपुरवासियों से अपील की है कि वे इस अभियान में भाग लेकर शहर को स्वच्छ, सुंदर और रंगीन बनाने में अपना योगदान दें।

जमवारामगढ़ में दो नाबालिग बच्चियों का बाल विवाह रुकवाया

प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण की तत्पर कार्रवाई, बच्चियों को बालिका गृह भेजा

प्रमोद कुमार, जयपुर

जयपुर जिले के जमवारामगढ़ क्षेत्र में मंगलवार देर रात प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त कार्रवाई में दो नाबालिग बच्चियों का बाल विवाह रुकवाया गया। जानकारी के अनुसार 5 और 8 वर्ष की बच्चियों का विवाह क्रमशः 9 और 11 वर्ष के बच्चों से किया जाना था। परिजनों ने कार्रवाई के डर से तय तारीख से एक दिन पहले ही फेरे कराने की तैयारी कर ली थी। मामले की सूचना मिलते ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश देकर विवाह रुकवाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पवन जीनवाल ने बताया कि उन्हें इस संबंध में

सूचना प्रयास संस्था से प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मामले की जानकारी रालसा को दी गई। रालसा के सदस्य सचिव हरिओम अत्री के निर्देश पर डीसीपीयू टीम को सक्रिय किया गया।

जमवारामगढ़ के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण लिंक मजिस्ट्रेट हुमा कौहरी ने रात में अपने निवास पर ही बाल विवाह निषेधाज्ञा आदेश पारित किया। इसके बाद टीम जयपुर से सरजौली पहुंची और परिजनों को समझाकर विवाह रुकवाया गया। इस दौरान प्रशासन, पुलिस और बाल संरक्षण इकाइयों की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों शादियों को रुकवाया गया। इसके बाद दोनों बच्चियों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया, जहां कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें बालिका गृह में सुरक्षित रखा गया है। प्रशासन ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि भविष्य में इस प्रकार का प्रयास करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध अतिक्रमण एवं निर्माणों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई जारी

14 करोड रूपये की बेशकीमती सरकारी भूमि को करवाया अतिक्रमण मुक्त

जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार, अतिक्रमण एवं अनियमितताओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस एवं सुशासन के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध अतिक्रमण एवं निर्माणों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशों पर प्रवर्तन शाखा द्वारा 29 अप्रैल, 2026 को विभिन्न जोनों में प्रवर्तन संबंधी कार्यवाहियां संपादित की गईं।

उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा ने बताया कि प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा जोन-17 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम दौलतपुरा बैनाड़, जिला जयपुर के खसरा नं. 717 व 718 में करीब 1.5 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई बाउंड्रीवाल, निर्माणाधीन ढांचा एवं अन्य अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया। कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन दस्ते द्वारा जोन-17 के राजस्व एवं तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर जेसीबी मशीन एवं मजदूरों की सहायता से समस्त अवैध निर्माण हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही जेडीए स्वामित्व के बोर्ड स्थापित किए गए। उक्त अतिक्रमण मुक्त भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये आंकी गई है।

प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा जोन-07 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित विधानसभा नगर धाबास, जिला जयपुर में करीब 500 वर्गगज सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर पेड़-पौधे लगाकर गार्डन विकसित किया गया था तथा पत्थर, मलबा एवं अन्य सामग्री डालकर कब्जा किया गया था। प्रवर्तन अधिकारी जोन-18 एवं 23 की मौजूदगी में जोन-07 के राजस्व एवं तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन एवं श्रमिकों की सहायता से समस्त अतिक्रमण हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही जेडीए स्वामित्व के बोर्ड लगाए गए। उक्त भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है।

प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा जोन-24 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम बस्सी रीको एरिया के पास जय अम्बे प्रथम कॉलोनी के प्लॉट नं. 28 में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ निर्मित अवैध फैक्ट्री के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

न्यूज इन बॉक्स

जयपुर की मेघा सोनी को मिला राष्ट्रीय रत्न सम्मान-2026

आधुनिक और पारंपरिक ज्वेलरी डिजाइन का कर रही काम; दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ आयोजन

जयपुर(नि.सं.)। जयपुर की युवा उद्यमी मेघा सोनी ने एक बार फिर शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। मेघा सोनी को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय रत्न सम्मान-2026 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान उभरते लक्जरी सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया।

देश की अलग-अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान

यह सम्मान मेघा सोनी को उनके चर्चित और तेजी से लोकप्रिय हो रहे सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड 'गजाह' के लिए दिया गया। कम समय में ही 'गजाह' ने सिल्वर ज्वेलरी सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई है। आधुनिक डिजाइनों, पारंपरिक भारतीय कला और उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण यह ब्रांड ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है और खासतौर पर महिलाओं की पहली पसंद बनकर उभरा है।

महिला उद्यमियों के लिए नए सत्र की प्रीव्यू मीट

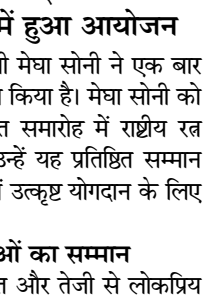

जयपुर(नि.सं.)। एफबीएस जयपुर की ओर से महिला उद्यमियों के लिए आयोजित नए सत्र की विशेष प्रीव्यू नेटवर्किंग मीट संपन्न हुई। इस आयोजन ने शहर की प्रतिभाशाली, उभरती और प्रेरणादायी महिला उद्यमियों को एक मंच पर एकत्रित कर सहयोग, संवाद और सशक्तिकरण का अनूठा अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत परिचय सत्र के साथ हुई, जहां सभी प्रतिभागियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र, अनुभव और व्यावसायिक दृष्टिकोण साझा किए। इस सत्र ने महिलाओं को एक-दूसरे के काम को समझने,अनुभवों से सीखने और संभावित सहयोग के नए आयाम तलाशने का अवसर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत से ही माहौल आत्मीय, ऊर्जावान और प्रेरणादायक बना रहा।

अजमेर में ग्राम रथ अभियान का हुआ शुभारंभ

जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचेगी गांव-गांव

जयपुर(नि.सं.)। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा कृषकों, पशुपालकों एवं ग्रामीण परिवारों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी अंतिम छोर तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को अजमेर सूचना केंद्र से ग्राम विकास रथ अभियान का शुभारंभ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी तथा जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने ग्राम विकास रथों को हरी

झंडी दिखाकर पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़ एवं केकड़ी विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अजमेर जिले में 15 दिवसीय एलईडी मोबाइल वैन आधारित जन-जागरूकता कार्यक्रम के रूप में ग्राम रथ अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में राज्य सरकार द्वारा कृषकों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी पहुंचाना तथा विकास कार्यों के संबंध में जनसुझाव प्राप्त करना है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जनहितकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

'अम्मा पद्मा ईश्वर म्यूजिक मेमोरियल'

अम्मा पद्मा ईश्वर की स्मृति में संगीत कार्यक्रम

जयपुर(नि.सं.)। मालवीय नगर स्थित दर्शक कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स के मिनी ऑडिटोरियम में संगीत, स्मृतियों और भावनाओं से भरी एक विशेष संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अम्मा पद्मा ईश्वर की स्मृति में आयोजित इस भावनात्मक कार्यक्रम ने श्रोताओं को भीतर तक छू लिया। 'अम्मा पद्मा ईश्वर म्यूजिक मेमोरियल' के अंतर्गत आयोजित इस श्रद्धांजलि संध्या में हर सुर, हर गीत और हर प्रस्तुति में अम्मा की उपस्थिति का अहसास जीवंत होता रहा। कार्यक्रम का वातावरण शुरू से ही आत्मीय, भावुक और संगीत की गहराई से भरा हुआ था। जैसे-जैसे एक के बाद एक गीत मंच से गूंजते गए, पूरा सभागार सुरों के साथ भावनाओं में डूबता चला गया। यह केवल एक संगीत संध्या नहीं, बल्कि स्मृतियों को स्वर देने और संगीत के माध्यम से जीवन को याद करने का एक मार्मिक प्रयास था। कार्यक्रम का सबसे भावुक और मार्मिक क्षण तब आया, जब अम्मा की पुत्री डॉ. रागिनी ईश्वर ने अपनी मां को याद करते हुए उनसे जुड़ी स्मृतियां साझा कीं।

लाडो प्रोत्साहन योजना में सीएमएचओ की मॉनिटरिंग फेल

10460 प्रसव में 1220 का वेरिफिकेशन अटका, 961 की किश्तें रुकीं

भरतपुर(वि.सं.)। लाडो प्रोत्साहन योजना में प्रसूताओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता अटक गई है। सीएमएचओ स्तर पर मॉनिटरिंग कमजोर रहने से वेरिफिकेशन समय पर नहीं हो पाया और इसका सीधा असर भुगतान पर पड़ा है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक जिले में 10460 बालिका जन्म (संस्थागत प्रसव) दर्ज हुए, लेकिन इनमें से सिर्फ 9240 मामलों का ही वेरिफिकेशन हो पाया, जबकि 1220 केस अब भी लंबित हैं। वेरिफिकेशन नहीं होने से इन प्रसूताओं को पहली किस्त तक नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत पीसीटीएस पोर्टल पर समय पर एंट्री नहीं होने और रिकॉर्ड अधूरे रहने की सामने आई है।

ऊर्जा मंत्री ने की बिजली वितरण निगमों की समीक्षा

डिस्कॉम्स विकसित करेंगे विकेन्द्रित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली

जयपुर(नि.सं.)। प्रदेश में डिस्कॉम्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अन्तर्गत उन क्षेत्रों में बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली विकसित किए जाने की योजना है, जहां पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों अथवा रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों से प्रचुर मात्रा में सरप्लस विकेन्द्रित सौर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इससे सुबह और शाम के पीक ऑवर्स की विद्युत सप्लाई को मेंटेन करने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मंगलवार को विद्युत भवन में बिजली वितरण निगमों कंपनियों की समीक्षा के दौरान इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे विद्युत आपूर्ति को बेहतर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टोरेज क्षमता का विस्तार आवश्यक है। शासन सचिव ऊर्जा एवं चेयरमैन डिस्कॉम्स सुश्री आरती डोगरा ने बैठक में बताया कि जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा उत्पादित विकेन्द्रित सौर ऊर्जा का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडअलोन डिसेन्ट्रलाइज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित किए जाएंगे। बैठक में ऊर्जा मंत्री ने स्मार्ट मीटरिंग, बिजली छीजत में कमी और गर्मी के दौरान विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की।

घरों से वेस्ट प्लास्टिक स्कूल लेकर पहुंचे बच्चे

स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका टीम को सौंपा, निस्तारण की नॉलेज ली

राजसमंद(वि.सं.)। राजसमंद के देवगढ़ कस्बे में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली। बुधवार को नगर पालिका देवगढ़ द्वारा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में प्लास्टिक संग्रहण उत्सव का आयोजन किया गया। अधिशासी अधिकारी पिंटू लाल जाट के निर्देशन में हुए इस अभियान में विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मेरा कचरा, मेरी जिम्मेदारी के संकल्प को साकार करते हुए बच्चों ने अपने घरों से प्लास्टिक कचरा, पुरानी बोतलें और सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रित कर नगर पालिका टीम को सौंपा।

बिजली बिल की टेंशन खत्म

11 लाख घरों में लगेंगे सोलर पैनल, बिल होगा 'जीरो'

केंद्र सरकार को भेजे दो चरणों के प्रस्ताव में पहले चरण को मिली सैद्धांतिक मंजूरी

- प्रदेश में **1210 मेगावाट** अतिरिक्त बिजली की क्षमता भी होगी विकसित

मनोहरसिंह खोखर । जयपुर

राज्य सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 11 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का प्रस्ताव दो चरणों में भेजा। इसमें जो सोलर पैनल लगेंगे, उनसे करीब 1210 मेगावाट क्षमता विकसित की जाएगी। अनुमानित लागत 6655 करोड़ रुपए है, जिसमें 3630 करोड़ रुपए केंद्र की सब्सिडी होगी, जबकि बाकी राशि राज्य सरकार और डिस्कॉम्स देंगे। राजस्थान में लागू 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली के नए फार्मूले के तहत 11 लाख उपभोक्ताओं की छत पर डिस्कॉम्स ही सोलर पैनल लगाएगा। पहले चरण में 3 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस पर 1300 से 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन उपभोक्ताओं को कोई राशि नहीं देनी होगी।

मुफ्त सोलर स्कीम का यह प्लान :

विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स) ही बैंक की ईएमआइ चुकाएंगी। फिर राज्य सरकार डिस्कॉम्स को राशि देगी। इनमें ऐसे उपभोक्ता शामिल हैं, जिनका मासिक बिजली उपभोग 150 यूनिट से कम है। प्रति पैनल लागत करीब 50 हजार रुपए आंकी गई है। योजना के तहत 33 हजार रुपए केंद्र सरकार की सब्सिडी होगी, जबकि बाकी 17 हजार रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। जयपुर, अजमेर, जोधपुर तीनों बिजली वितरण कंपनियों में कितने और किन-किन उपभोक्ताओं के सोलन पैनल लगेंगे, यह अब तय किया जायेगा।

1.1 किलोवाट से हर दिन 5 यूनिट उत्पादन :

सोलर पैनल से बिजली उत्पादन अलग-अलग क्षेत्रों पर निर्भर करता रहा है। पश्चिमी राजस्थान में औसतन उत्पादन ज्यादा है, जबकि अन्य जिलों में अलग। सोलर विशेषज्ञ 1.1 किलोवाट से औसतन 4.4 से 5 यूनिट तक प्रतिदिन बिजली उत्पादन मानते हैं। यह मानें तो इससे प्रतिमाह 132 से 150 यूनिट उत्पादन होगा। ऐसी स्थिति में बिजली बिल शून्य रहेगा। डेढ सौ यूनिट तक खपत वाले उन उपभोक्ताओं को 1 रुपए यूनिट का इन्सेंटिव दिया जाएगा,जो बिजली बचाएंगे। जितनी यूनिट बिजली बचेगी, उसमें से एक रुपए यूनिट मीटर चार्ज में से कम कर दिया जाएगा। अधिकतम 75 रुपए होगा।

यह है योजना :

इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने के लिए अपनी ओर से कोई राशि नहीं देनी होगी। डिस्कॉम ही 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाएगा। योजना को दो चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है। पहले चरण में 6 लाख और दूसरे चरण में 5 लाख घरों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 6,655 करोड़ है। इसमें से 3,630 करोड़ केंद्र सरकार की सब्सिडी से और शेष राशि राज्य सरकार व डिस्कॉम द्वारा वहन की जाएगी। यह योजना विशेष रूप से उन 11 लाख परिवारों के लिए है जिनका मासिक बिजली उपभोग 150 यूनिट से कम है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत उपभोक्ता अपनी पात्रता जाँच कर इसके लिए सहमति दे सकते हैं।

सोलर सब्सिडी का गणित :

यदि आप स्वयं पैनल लगवाना चाहते हैं, तो आप पीएम सूर्य घर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार की सब्सिडी 33,000 (1.1 द्बङ्क के लिए) या अधिकतम 78,000 (3 द्बङ्क तक)। राजस्थान सरकार 17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी और एक स्मार्ट मीटर निःशुल्क प्रदान कर रही है।
यानि 1.1 किलोवाट सिस्टम पर कुल 50,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है।

उपभोक्ता को लाभ और ऊर्जा क्षेत्र मजबूत :

"राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए हम बिजली लागत कम करने और डिस्कॉम्स की स्थिति सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी दिशा में केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव पर सहमति दी है। इससे जरूरतमंद उपभोक्ता को स्थाई लाभ मिलेगा और ऊर्जा क्षेत्र मजबूत होगा।

-हीरालाल नागर, ऊर्जा मंत्री

एसएमएस अस्पताल का इएनटी विभाग में अपग्रेडेशन, मंत्री सिंह खींवसर ने किया लोकार्पण

लोक टुडे। जयपुर

सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध एसएमएस अस्पताल के ईएनटी विभाग में आधुनिक सुविधाओं के उन्नयन एवं विस्तार का लोकार्पण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा बुधवार को किया गया। इस अवसर पर मंत्री खींवसर ने कहा कि इस प्रकार के विकास कार्य न केवल मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराते हैं, बल्कि यूजी एवं पीजी विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा को भी सुदृढ़ बनाते हैं। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार प्रदेश की आम जनता को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे प्रयास राजस्थान को चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. पवन सिंघल ने विभाग में हुए व्यापक सुधारों की जानकारी देते हुए बताया कि मरीजों की देखभाल, शिक्षण, स्टाफ

सुदृढ़ीकरण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग में अत्याधुनिक कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन थिएटर की स्थापना की गई है, जहां जटिल कान सर्जरी एवं श्रवण क्षमता बहाली से संबंधित ऑपरेशन किए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि 800 वर्ग फीट क्षेत्र में 10 स्टेशनों वाला आधुनिक स्किल लैब स्थापित किया गया है, जहां रेजिडेंट डॉक्टरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही, वर्टिगो जैसे रोगों के समग्र उपचार हेतु न्यूरो-ऑटोलॉजी लैब भी विकसित की गई है। विभाग में ओपीडी एवं ओटी ब्लॉक का नवीनीकरण किया गया है तथा सियालोएंडोस्कोपी सेट सहित कई आधुनिक उपकरण जोड़े गए हैं। ऑडियोलॉजी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए नए कक्ष, उन्नत मशीनें तथा 5 ऑडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त, 8 कक्षों वाला ऑडियोलॉजी विंग भी विकसित किया गया है। डॉ. सिंघल ने बताया कि विभाग में अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिनके तहत दो ऑडियोलॉजिस्ट को कार्यमुक्त भी किया गया है। यह उन्नयन ईएनटी विभाग को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आधुनिक चिकित्सा सेवाओं एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। इस अवसर पर प्रिंसिपल कंट्रोलर डॉ. दीपक माहेश्वरी, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. मृणाल जोशी, बड़ी संख्या में समाज सेवी, चिकित्सक एवं रेजिडेंट उपस्थित रहे।

प्रदेश का सबसे बड़ा कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र कुंडा की ढाणी में स्थापित

लोक टुडे। जयपुर

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर जिला विद्युत सर्किल उत्तर के कुंडा की ढ़ाणी में स्थापित हुआ। करीब 4.9 मेगावाट क्षमता का यह सौर ऊर्जा संयंत्र कुंडा की ढ़ाणी विद्युत सब डिविजन के ताला स्थित 33 केवी सब स्टेशन से जुड़े गांव डेकला में स्थापित हुआ है। लगभग 24 बीघा भूमि पर फैले इस संयंत्र से 437 कृषि उपभोक्ताओं को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली सुलभ हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि कंपोनेंट-सी के अन्तर्गत अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रावधान है। राज्य में अब तक पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट-ए एवं कंपोनेंट-सी के अन्तर्गत 4027 मेगावाट क्षमता के कुल 1819 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इन सभी में यह सर्वाधिक क्षमता का संयंत्र है। इससे प्रतिदिन औसतन 25 हजार यूनिट बिजली उत्पन्न होने का अनुमान है। इससे पहले अजमेर डिस्कॉम में 4.84 मेगावाट क्षमता का सर्वाधिक बड़ा प्लांट था।

पायलट पर टिप्पणी का विरोध ; अजमेर में फूंका भाजपा प्रभारी का पुतला

नितिन मेहरा। अजमेर

राजस्थान की सियासत में जुबानी जंग अब सड़कों पर उतर चुकी है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट पर की गई विवादित टिप्पणी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध तोड़ दिया है। बुधवार को अजमेर के गांधी भवन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी जननेता के लिए अभद्र और निजी टिप्पणी करना कतई स्वीकार्य नहीं है। कार्यकर्ताओं ने इसे राजस्थान के बेटे का अपमान करार देते हुए भाजपा आलाकमान से जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि विवाद की जड़ भाजपा प्रभारी का वह बयान है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सचिन पायलट के वजूद और उनकी राजनीतिक निष्ठा पर तीखे सवाल उठाए थे। अजमेर में हुए इस प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भाजपा नेता मुद्दों की कमी के कारण अब व्यक्तिगत हमले पर उतर आए हैं, जो उनकी हताशा को दर्शाता है। अजमेर के इस विरोध प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। कांग्रेस ने दो टूक चेतावनी दी है कि जब तक राधामोहन दास अपने शब्दों को वापस लेकर माफी नहीं मांगते, तब तक उनका हर दौरे पर इसी तरह काले झंडों और पुतला दहन के साथ स्वागत किया जाएगा।

आसाराम को राहत ; हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत 25 मई तक बढ़ाई

लोक टुडे। जोधपुर

यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि 25 मई तक बढ़ा दी है। आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की अर्जी पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कार्यवाहक सीजे एसपी शर्मा, जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बैंच ने आसाराम की जमानत अवधि 25 मई तक बढ़ाने के आदेश दिए। बता दें कि आसाराम को 29 अक्टूबर 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट से 6 महीने की राहत मिली थी, लेकिन 29 अप्रेल को जमानत अवधि खत्म होने से पहले मंगलवार को हाईकोर्ट में आसाराम के वकीलों ने प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमें आसाराम की खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी।

जीतू मुंडा केस में मंत्री किरोड़ीलाल की संवेदनशील पहल : एक महीने की सैलरी देने की घोषणा

लोक टुडे। जयपुर

ओडिशा के चर्चित जीतू मुंडा केस ने अब सियासी रंग भी पकड़ लिया है। एक तरफ जहां इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, वहीं अब राजस्थान सरकार के मंत्री ने इस मामले पर बड़ा बयान देते हुए संवेदनशील पहल की है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जीतू मुंडा की पीड़ा को अमानवीय और शर्मनाक बताया। उन्होंने लिखा कि एक गरीब आदिवासी को कागजी खानापूर्ति के नाम पर इस तरह परेशान करना किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री से इस मामले में तत्काल और कठोर कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, मंत्री मीणा ने जीतू मुंडा और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि 'जीतू

मुंडा का दर्द मेरा दर्द है' और संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़ा रहना उनका कर्तव्य है। इसी भावना के तहत उन्होंने अपनी एक महीने की सैलरी पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह राशि जल्द ही परिवार तक पहुंचाई जाएगी।

बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया था जीतू मुंडा :

गौरतलब है कि ओडिशा में जीतू मुंडा का मामला उस समय सुर्खियों में आया, जब वह अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि बैंक द्वारा आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने के बाद मजबूरी में उसने यह कदम उठाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस घटना के बाद देशभर में सिस्टम और संवेदनशीलता को लेकर बहस छिड़ गई है। अब राजस्थान के मंत्री के इस कदम ने मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया है।

अब सहायता के लिए आगे आए हाथ :

इस मार्मिक घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अलख पांडे ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए जीतू मुंडा की सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। अलख पांडे (फिजिक्स वाला) ने ओडिशा के जीतू मुंडा की मदद के लिए 10 लाख दान करने की घोषणा की है। वहीं जिला प्रशासन (क्योंझर, ओडिशा) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता (रेड क्रॉस फंड से) प्रदान की है।

आरजीएचएस पर गहराया संकट : 2200 करोड़ का भुगतान अटका, अस्पतालों ने सेवाएं रोकी

मरीजों को जेब से इलाज कराने की मजबूरी, सरकार की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल

प्रमोद कुमार। जयपुर

राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी आरजीएचएस इन दिनों गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जारी बयान के अनुसार योजना के तहत अस्पतालों, डायग्नोस्टिक केंद्रों और दवा विक्रेताओं के करीब 2200 करोड़ से अधिक भुगतान पिछले 8-9 महीनों से लंबित हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था चरमरा गई है। कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) के गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि स्थिति यह है कि भुगतान नहीं मिलने से सेवा प्रदाताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। जबकि दूसरी ओर कर्मचारियों और पेंशनर्स को नियमित कटौती के बावजूद सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा।

निजी खर्च पर करवा रहे इलाज :

कई लाभार्थियों को निजी खर्च पर इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। योजना से जुड़े अस्पताल पहले भी विरोध जता चुके हैं। सितंबर 2025 में आंशिक सेवाएं बंद करने के बाद अब 13 अप्रैल 2026 से कई अस्पतालों ने योजना का बहिष्कार शुरू कर दिया है। केमिस्ट एसोसिएशन और कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आईएमए राजस्थान के अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि वित्त, स्वास्थ्य विभाग और आरजीएचएस एजेंसी के बीच समन्वय की कमी के चलते समाधान नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उच्च स्तरीय समिति गठित कर त्वरित निर्णय लेने की मांग की है।

अस्पतालों पर आर्थिक दबाव बढ़ा :

आईएमए के सचिव डॉ. एनके अग्रवाल ने कहा कि कम पैकेज दरें, सीमित एम्पैनलमेंट और पुरानी सीजीएचएस दरें 2014 लागू होने से अस्पतालों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार योजना को इंश्योरेंस मोड में ले जाने पर विचार कर रही है, जिससे हितधारकों की चिंता और बढ़ गई है। आईएमए ने कहा है कि जब तक ठोस सुधार नहीं होंगे, तब तक बहिष्कार जारी रहेगा।